ARUNACHALAM): (a) to (d) No, Sir. The amount allocated, for Khadi and Village Industries Sector through Khadi and Village Industries Commission for the last three years for development of rural industries are given below:—

Year	Amount (Rs. in lakhs)
1992-93	193.00 (Actuals)
1993-94	208.00 (Actuals)
1994-95	214.00 (Budget Estimate)

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकरण

4141. **श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला:** क्या **प्रधान मंत्री** 11 अगस्त, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2363 के दिये गये उत्तर को देखेंगे कि और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने रुग्ण उपक्रमों को बन्द कर दिया गया है/बंद किये जाने की संभावना है;

(ग) उनकी रुग्णता के प्रमुख कारण क्या हैं और उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या उन रुग्ण एककों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन मामलों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड को भेजा गया है और यदि हां, तो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड ने इस संबंध में क्या सिफारिशें की हैं; और

(च) गुजरात में किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) 31 मार्च, 1993 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के/उपक्रमों के पंजीकृत कार्यालय गुजरात/दो राज्य में अवस्थित थे। विगत तीन वर्षों के लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

		निवल लाभ/घाटा		
		1992-93	1991-92	1990-91
1.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो० लि०	13177	5502	5727
2.	एन०टी०सी० (गुजरात) लि०	-8385	-3713	-2195

(ख) से (च) एन०टी०सी० (गुजरात) लि० एक रुग्ण उद्यम है एवं इसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल में पंजीकृत कर दिया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं तैयार करने के लिए प्रचालन अभिकरण की नियुक्ति की है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 9 अप्रैल, 1994 को विशिष्ट त्रिपक्षीय समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें श्रमिक संघ, प्रबन्धन तथा सरकार के प्रतिनिधियों में एन०टी०सी० के सभी कारखानों का पुनरुद्धार करने पर सहमति हो गई थी। पुरानी तथा अप्रचलित मशीनें, पुरानी प्रोद्योगिकी, श्रमिकों का बाहुल्य आदि रुग्णता के मुख्य कारण हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के अंतिम निर्णय की अब भी प्रतीक्षा की जा रही है। कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया गया है। वर्तमानः, गुजरात स्थित किसी सरकारी उद्यम के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।